742 करोड़ का चंदा मिला भारतीय जनता पार्टी को वित्त वर्ष 2018–19 में। इसी समयावधि में कांग्रेस को 148 करोड़ रुपये बतौर चंदा मिला। यह आंकड़ा एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने संकलित किया है।

पुलवामा ने बदला सीमापार की चुनौती से निपटने का सिद्धांत

बोले राजनाथ ▸ पाक समझ ले कि सीमापार के आतंकी ठिकाने भी अब सुरक्षित नहीं

रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ साल में सुरक्षा को लेकर माहौल बदल गया है

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ ने शुक्रवार को कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत को सीमापार की चुनौतियों को लेकर अपने सुरक्षा सिद्धांतों (डॉक्टरीन) को फिर से लिखने के लिए बाध्य किया। बालाकोट ने हमारे संकल्प और क्षमता दोनों को दिखाते हुए पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया। रक्षा मंत्री ने बुधवार को भी एक ट्वीट करके आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया था।

बालाकोट एयरस्ट्राइक की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक विशेष सेमिनार में राजनाथ ने कहा कि बालाकोट एयरस्ट्राइक के जरिये भारत ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश दे दिया है कि सीमापार के आतंकी ठिकाने भी अब आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं हैं। भारत के खिलाफ आतंकवाद को पाकिस्तान एक सस्ते विकल्प के रूप में इस्तेमाल करता रहा था, मगर बालाकोट में सबक सिखाकर हमने साफ कर दिया है कि आतंकवादी घटनाओं के लिए उसे अब बड़ी कीमत चुकानी होगी। बालाकोट जाहिर करता है कि भारत अपने सबसे सटीक संसाधनों का इस्तेमाल करके निर्धारित लक्ष्यों पर निशाना साध सकता है। इसमें इनोवेशन और विरोधी को चौंकाने वाला तत्व हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले कुछ साल में सुरक्षा को लेकर माहौल बदल गया है। कारगिल और सीमापार आतंकवाद की घटनाएं नए तरह के युद्ध के उदाहरण हैं। लिहाजा, हाइब्रिड युद्ध आज की वास्तविकता है। टकराव के इस नए बदलते माहौल में कोई स्पष्ट आगाज और अंत नहीं है।

इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमें जो लक्ष्य सौंपे गए हैं उसके लिए सीमापार से घुसपैठ पर अंकुश लगाना अहम है। इसके लिए जमीन, आकाश और समुद्र सभी रास्तों पर घुसपैठ के खिलाफ चौकसी को हर पल सतर्कता के स्तर पर ले जाना है। हर कर्मचारी को इसके लिए प्रशिक्षण और प्रेरणा की जरूरत है। चुनौती का विश्वसनीय समाधान सैन्य नेतृत्व और कड़े फैसले लेने वाले राजनीतिक नेतृत्व से आता है। कारगिल, उड़ी और पुलवामा हमलों के मामलों में यह देखा गया है।

नई दिल्ली में आयोजित सेंटर फॉर एयर स्टडीज के दौरान (दाएं से) नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. जी सतीश रेड्डी और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज के महानिदेशक केके नौहवार। एएनआइ

बालाकोट के दौरान कर सकते थे ज्यादा विमानों का इस्तेमाल : वायुसेना प्रमुख

नई दिल्ली, एजेंसियां : वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने शुक्रवार को बताया कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान वायुसेना दोगुनी संख्या में युद्धक विमानों और चार गुना हथियारों का इस्तेमाल कर सकती थी, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया ताकि नुकसान कम से कम हो।

सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज द्वारा आयोजित एक सेमिनार में वायुसेना प्रमुख ने कहा, 'एक साल पहले सरकार ने नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान स्थित आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर स्ट्राइक करने का कड़ा और साहसी फैसला लिया था। वायुसेना ने चुने हुए लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। पाकिस्तानी वायुसेना ने 30 घंटे बाद ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के तहत बड़ी संख्या में युद्धक विमानों के साथ जवाबी कार्रवाई की। लेकिन भारतीय वायुसेना ने उन्हें उनके लक्ष्य नहीं भेदने दिए। वे संघर्ष खत्म करने की जल्दी में थे। यह सब वे अपने नागरिकों को दिखाने के लिए कर रहे थे।' एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि पहले उप-पारंपरिक लड़ाई में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, लेकिन बालाकोट एयर स्ट्राइक ने इस दिशा में बुनियादी बदलाव किया है।

वायुसेना प्रमुख ने आगे कहा, 'कारगिल युद्ध के समय बियांड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता के कारण हमें पाकिस्तानी वायुसेना के ऊपर बढ़त हासिल थी। हमने उसे गंवा दिया था और उसके बाद बेहतर क्षमता हासिल करने के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू करने में डेढ़ दशक का समय लग गया।'

'पाक करता रहे परमाणु हथियारों की बात' : वायुसेना के उपप्रमुख एयर मार्शल एचएस अरोड़ा ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता और जवाबी हमले की बात करता रह सकता है। लेकिन भारत के पास भी वैसी क्षमता है। हालांकि भारत की इस संबंध में पहले इस्तेमाल नहीं करने की नीति है।

हमले के आरोपित को जमानत सरकार की घोर नाकामी : कांग्रेस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पुलवामा आतंकी हमले की साजिश के आरोपी यूसुफ चोपान को मिली जमानत को कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और एनआइए प्रमुख की बड़ी नाकामी करार दिया है। पार्टी ने जैश-ए-मुहम्मद से ताल्लुक रखने वाले चोपान के जमानत पर रिहा होने को पुलवामा में शहीद 44 जवानों की शहादत का अपमान बताते हुए गृहमंत्री और एनआइए प्रमुख के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही पुलवामा हमले की साजिश से जुड़े मुकदमे में चोपान के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होने का हलफनामा दायर करने को लेकर सरकार को भी आड़े हाथों लिया है।

कांग्रेस ने यूसुफ चोपान को जमानत मिलने की खबरों को दबाने के लिए सरकार पर भ्रम फैलाने और दुष्प्रचार का आरोप भी लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कांफ्रेंस में इसको लेकर सरकार, गृहमंत्री और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) प्रमुख पर दर्जन भर से ज्यादा सवालों की बौछार करते हुए कहा कि इनकी नाकामी की वजह से जैश के आतंकवादी छूट रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि चोपान जैश का सदस्य है जो देश में कई आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है।

न्यूज गैलरी

जीएसटी सहायक आयुक्त के खिलाफ भ्रष्टाचार का केस

नई दिल्ली : सीबीआइ ने जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त दीपक पंडित के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ ज्ञात स्रोतों से 376 फीसद अधिक करीब 3.96 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। दीपक पंडित फिल्मी शख्सियत अशोक पंडित के करीबी रिश्तेदार हैं। सीबीआइ एफआइआर के मुताबिक दीपक ने अपने पद का दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार के जरिये उक्त संपत्तियां अर्जित कीं। सीबीआइ ने दीपक पंडित के साथ-साथ उनकी पत्नी आरुषि और दो पुत्रों आशुतोष और दिव्यांश के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने गुरुवार को सात रिहाइशी परिसरों की तलाशी ली थी जो दीपक पंडित और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर हैं। इनमें छह रिहाइशी परिसर मुंबई में और एक भुवनेश्वर में हैं। (प्रेट्र)

'जब होटल भरे हुए हैं तो अर्थव्यवस्था विफल कैसे'

पणजी : जो लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के विफल होने का दावा कर रहे हैं वे गलत हैं। इसका उदाहरण मैरेज हॉल और होटल हैं जो अपनी पूरी क्षमता से फुल चल रहे हैं। केंद्रीय रेल राज्यमंत्री सुरेश अंगड़ी ने शुक्रवार को यह दावा किया। पणजी के समीप एक रिसोर्ट में टेक्निकल सेमिनार को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'अधिकांश मीडिया, अधिकांश लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था विफल है। आप बस कल्पना करें कि आप किसी होटल में जाते हैं, आप किसी मैरेज हॉल में जाते हैं, आप किसी विमान में जाते हैं, यहां तक कि रेलवे ... हर रोज (वहां) शिकायत मिलती है।' उन्होंने कहा, 'जब आपको जगह नहीं मिलती है तो इसका अर्थ यह है कि वहां मांग बनी हुई है, इसलिए जब इतनी मांग है तो अर्थव्यवस्था कहां विफल है?' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को अपने निर्माण क्षेत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। (आइएएनएस)

अब गरीबरथ एक्सप्रेस में अनिवार्य हुआ बेड रोल लेना

बरेली : रेलवे ने दुरंतो और अन्य मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की तरह अब गरीब रथ में भी यात्रियों के लिए बेडरोल लेना जरूरी कर दिया है। इसका किराया टिकट के साथ देना होगा। मुरादाबाद की सीनियर डिवीजनल कॉमर्शियल मैनेजर रेखा शर्मा ने बताया कि यह व्यवस्था 15 मई से लागू होगी। अभी तक गरीबरथ में यह व्यवस्था वैकल्पिक होती थी। ट्रेन से बेड रोल चोरी होने के मामले बढ़े तो रेलवे ने हरेक यात्री को यह देने का नियम बनाया। जब हरेक यात्री के पास बेड रोड होगा तो उसे वापस करने की जिम्मेदारी भी होगी। (जासं)

बिहार और ओडिशा ने उठाई विशेष दर्जे की मांग

जागरण टीम, भुवनेश्वर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई 24वीं पूर्वांचल क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य को जहां विशेष दर्जा दिए जाने की मांग दोहराई, वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया।

इस उच्च स्तरीय बैठक में बिहार, ओडिशा और बंगाल के मुख्यमंत्री जबकि झारखंड के वित्तमंत्री रामेश्वर उरांव शामिल हुए। नीतीश ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोहरे अंक की विकास दर हासिल करने के बावजूद विकास के प्रमुख मापदंडों जैसे गरीबी रेखा, प्रति व्यक्ति आय, औद्योगीकरण तथा भौतिक आधारभूत संरचना में बिहार राष्ट्रीय औसत से नीचे है।

ऐसी स्थिति देश के कई अन्य राज्यों की भी है। इसलिए इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है, ताकि वे देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकें। नीतीश ने कहा कि गंगा नदी की अविरलता को बरकरार रखने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक गाद प्रबंधन नीति की आवश्यकता है। यह पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल हो। उन्होंने पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि (बीआरजीएफ) के तहत बकाया राशि जारी करने का मामला उठाया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ ही विशेष आर्थिक पैकेज देने के लिए भी अनुरोध किया।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुक्रवार को भुवनेश्वर स्थित अपने आवास पर लंच का आयोजन करके धुर विरोधी गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक मेज पर लाने का काम किया। लंच में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। भुवनेश्वर में सभी नेता जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक के सिलसिले में जुटे थे। प्रेट्र

जीएसटी का मुद्दा उठा : बैठक में जीएसटी का मुद्दा भी उठा। ममता बनर्जी ने कहा कि जीएसटी के बावत मिलनी वाली राशि प्रत्येक महीने देने के बजाय छह महीने में दी जा रही है। छह महीने में पैसा मिलने पर हम कर्मचारियों का वेतन किस प्रकार से देंगे। बंगाल को केंद्र से 50 हजार करोड़ रुपये मिलना है। इस राशि को जल्द से मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए। ममता ने कहा कि चक्रवात फणि, बुलबुल में बंगाल में व्यापक नुकसान हुआ था, मगर हमें आज तक नुकसान की राशि नहीं मिली है। ममता बनर्जी ने बाद में पत्रकारों से कहा कि बैठक में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) पर कोई चर्चा नहीं हुई लेकिन उन्होंने दिल्ली में हिंसा का मुद्दा उठाते हुए गृहमंत्री से शांति बहाली के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की ताकि स्थिति और न बिगड़े। उन्होंने हिंसा पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने की भी मांग की। ममता ने कहा-'दिल्ली में जो कुछ हुआ, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और उससे मैं बहुत दुखी हूं। दिल्ली सहित देशभर में शांति कायम होनी चाहिए।'

एक टेबल पर खाया खाना : बैठक के बाद नवीन पटनायक के आवास पर गृहमंत्री अमित शाह, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक साथ बैठकर दोपहर का भोजन किया।

कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले– ममता व मोदी के बीच साठगांठ

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

अधीर रंजन। फाइल

अमित शाह के साथ बनर्जी की बैठक को लेकर कांग्रेस सांसद ने बोला हमला

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भुवनेश्वर में शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई पूर्वी क्षेत्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शिरकत करने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता व मोदी के बीच साठगांठ है। ममता सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए केंद्र का विरोध करती हैं। ममता खुद को बचाने में व्यस्त हैं। उन्हें दिल्ली में हुई हिंसा की घटनाओं से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ दिखावे के लिए उसपर आंसू बहा रही हैं।

अधीर ने यह भी कहा कि सारधा चिटफंड मामले में आइपीएस अधिकारी राजीव कुमार पर जब गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी, तब उन्हें बचाने के लिए ममता दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गई थीं। इसके बाद पीएम ने उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री के पास भेज दिया था। अमित शाह से ममता की मुलाकात के बाद राजीव कुमार सीबीआइ की गिरफ्तारी से बच गए थे। अधीर ने सारधा व नारदा मामले की जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ममता व केंद्र के बीच मिलीभगत के चलते सीबीआइ चुप है। गौरतलब है कि दिल्ली की हिंसा को लेकर अधीर ने भुवनेश्वर में होने वाली बैठक रद करने की मांग की थी।

दूसरी ओर, पूर्व माकपा सांसद मुहम्मद सलीम ने भी गृह मंत्री के साथ बैठक को लेकर ममता पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली हिंसा पर ममता जो कुछ बोल रही हैं, वह महज दिखावा है। वहीं, विधानसभा में माकपा विधायक दल के नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि कितनी शर्मनाक बात है कि दिल्ली जल रही है और अमित शाह एक मार्च को बंगाल में सभा करने आ रहे हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली में हुई हिंसा के लिए केंद्र व भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए शुक्रवार को कहा कि यह धर्म के नाम पर देश को बांटने की साजिश है।

साठ के पार लोगों को राष्ट्रहित के कामों से जोड़ेगी सरकार

अरविंद पांडेय, नई दिल्ली

बुढ़ापा नहीं बोझ

- प्रधानमंत्री आज प्रयागराज से कर सकते हैं योजना का एलान
- सरकार ने बनाई योजना, तीन लाख ऐसे बुजुर्गों की हुई पहचान

सेवानिवृत्ति या फिर साठ की उम्र पार होने के बाद भी यदि आप स्वस्थ हैं और सक्रिय हैं, तो अब आप पर बुढ़ापा भारी नहीं पड़ने वाला है। सरकार ने ऐसे सभी सक्रिय बुजुर्गों को अब राष्ट्रहित से जुड़े कामों से जोड़ने का फैसला लिया है। इसके तहत इन सभी को इनकी पसंद और अनुभव से जुड़े कामों से संबद्ध किया जाएगा। इससे जहां सरकार, देश और समाज को इनके लंबे अनुभव का फायदा मिलेगा, वहीं इन पर भी बुढ़ापे का असर जल्दी नहीं छाएगा। वह एक लंबा सक्रिय जीवन बिता सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को प्रयागराज मे आयोजित वयोश्री योजना के तहत लगाए मेगा कैंप में इसका एलान कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में सक्रिय सरकार ने फिलहाल इस दिशा में एक नई पहल शुरू करने की तैयारी की है। इसके तहत देश भर के करीब तीन लाख ऐसे बुजुर्गों की पहचान भी की गई है, जो सक्रिय हैं और उनमें कुछ करने का जुनून भी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक अब इन सभी को अलग-अलग क्षेत्रों में चल रही सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसका भी एक एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। सरकार ने यह पहल तब शुरू की है, जब बड़ी संख्या में सक्रिय बुजुर्गों ने सरकार से उनकी योजनाओं में हाथ बंटाने की इच्छा जताई है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस ग्रामीण क्षेत्रों की ओर है। जहां अभी विकास योजनाएं बेहतर तरीके से नहीं पहुंच पा रही हैं। बुजुर्ग अपने अनुभव के जरिए इसे लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकते हैं।

गौरतलब है कि जापान में बुर्जुगों को नए जॉब दिए जा रहे हैं। शायद भारत ने भी इससे सीख ली है। मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या करीब 15 करोड़ है, जो तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2025 तक यह संख्या 20 करोड़ के आसपास पहुंचने का अनुमान है। हालांकि मौजूदा समय में इनकी जो संख्या है, उनमें करीब दस करोड़ वरिष्ठ नागरिक सक्रिय हैं। केंद्र सरकार अब इन्हें ही विकास की मुख्य धारा ने जोड़ने की योजना को लेकर काम कर रही है।

फांसी से बचने के लिए निर्भया के गुनहगार पवन ने दाखिल की क्यूरेटिव याचिका

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- निचली अदालत ने तीन मार्च तय की है चारों दोषियों को फांसी देने की तिथि
- फांसी की सजा को शीर्ष अदालत में फिर दी चुनौती

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषी पवन गुप्ता ने फांसी से बचने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फांसी की तारीख नजदीक आती देख पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर मृत्युदंड को चुनौती दी है। याचिका में पवन ने तीन मार्च को होने वाली फांसी पर रोक लगाए जाने की मांग भी की है।

निर्भया कांड के चारों दोषियों में से पवन गुप्ता ही एक मात्र दोषी है जिसने अभी तक क्यूरेटिव और दया याचिकाएं दाखिल नहीं की थीं। इसके अलावा बाकी के तीन दोषियों के सारे कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। उनकी क्यूरेटिव और दया याचिकाएं तक खारिज हो चुकी हैं। निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तीन मार्च को सुबह छह बजे का वक्त तय कर रखा है।

पवन के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने की जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक पवन के सारे कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हुए हैं। एपी सिंह ने कहा, पवन की क्यूरेटिव याचिका में अनुरोध किया गया है कि नए तथ्यों को देखते हुए मामले पर विचार किया जाए। याचिका में फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग करते हुए कहा गया है कि पवन अपराध के वक्त नाबालिग था, इस तथ्य पर विचार होना चाहिए। एपी सिंह ने यह भी कहा कि पवन अपराध के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसी कई चीजें हैं जिन पर सुनवाई के दौरान गौर नहीं किया गया है।

मालूम हो कि 16 दिसंबर, 2012 की रात दिल्ली में चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। इस दौरान छात्रा से इस कदर दरिंदगी हुई थी कि बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी की सजा सुनाई गई है। कोर्ट चारों की पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज कर चुका है। इनमें से तीन दोषियों मुकेश, अक्षय और विनय के सारे कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। राष्ट्रपति तक से दया याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। पवन ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल नहीं की थी। शुक्रवार को उसने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर दी। हालांकि अभी भी उसने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल नहीं की है। वैसे हाई कोर्ट ने सभी दोषियों को एक साथ फांसी देने के आदेश में दोषियों को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए सात दिन का समय दिया था और सात दिन का समय समाप्त होने के बाद निचली अदालत ने चारों दोषियों को फांसी देने के लिए तीन मार्च सुबह छह बजे का ब्लैक वारंट जारी किया है। लेकिन दोषी कानूनी पेचीदिगियों का लाभ उठाकर मौत से बचने के लिए लगातार देरी कर रहे हैं।

उधर, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक याचिका दाखिल करके सभी दोषियों को एक साथ फांसी देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रखी है। सरकार का कहना है कि जिन दोषियों के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं उनकी सजा पर अमल की इजाजत दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि इस याचिका के लंबित रहने का निचली अदालत से दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पांच मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी थी।

तेलंगाना मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इन्कार

नई दिल्ली, एजेंसियां : प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना मुठभेड़ में मारे गए आरोपितों के परिजनों को मुआवजा और पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इन्कार कर दिया।

पिछले साल 27 नवंबर की रात को 26 साल की डॉक्टर की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपितों को पकड़ा था। बाद में घटनाक्रम की जांच के सिलसिले में पुलिस आरोपितों को वारदात स्थल पर ले गई थी, जहां से उन्होंने भागने की कोशिश की और मारे गए थे। पीठ ने कहा कि इस मामले की तीन सदस्यीय कमेटी जांच कर रही है। आरोपितों के परिजन साक्ष्यों के साथ कमेटी से संपर्क करें और कमेटी की रिपोर्ट के बाद वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पीठ ने परिजनों से कमेटी की रिपोर्ट आने तक इंतजार करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने 2015 के गुजरात पाटीदार आंदोलन मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को छह मार्च तक अग्रिम जमानत दे दी है। अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद करने की मांग वाली पटेल की याचिका पर शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को नोटिस भी जारी किया है।

उपलब्धि

बिना रुके 10,000 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है यह जहाज, केंद्रीय जहाजरानी मंत्री ने तटरक्षक बल में कराया शामिल

समुद्र की सुरक्षा में तैनात हुआ अत्याधुनिक जहाज 'वरद'

चेन्नई, प्रेट्र : केंद्रीय जहाजरानी मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई के बंदरगाह पर आयोजित एक समारोह में समुद्र की निगरानी के लिए तैयार 'वरद' नामक जहाज को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कराया। 98 मीटर लंबे इस जहाज का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो ने चेन्नई के करीब कट्टूपल्ली स्थित यार्ड में किया है।

'वरद' पर आधुनिक नौवहन और संचार उपकरण, 30 एमएम और 12.7 एमएम की तोपें, समेकित पुल प्रणाली, परमाणु ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली और आग से मुकाबले के लिए उच्च क्षमता वाली प्रणाली लगाई गई हैं। यह जहाज दो इंजन वाले हल्के हेलीकॉप्टरों का परिवहन कर सकता है और रात में भी उनकी उड़ान की इजाजत देता है। जहाज पर तेजगति वाली चार नावें उपलब्ध रहेंगी। दो इंजन वाले इस जहाज की अधिकतम गति 26 नॉटिकल मील (करीब 48 किलोमीटर) प्रति घंटा है। जहाज को फिलहाल कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन (उत्तर पूर्व) के अंतर्गत पारादीप में तैनात किया गया है। इस पर 11 अधिकारी और 91 जवान तैनात हैं। कमांडर पिंटू बाग इसके कमांडिंग ऑफिसर बनाए गए हैं।

चेन्नई में शुक्रवार को केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारतीय तटरक्षक बल के नए गश्ती पोत वरद का जलावतरण किया। उनके साथ तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन हैं (बाएं)। प्रेट्र

मंत्री मंडाविया ने तटरक्षक बल की सेवाओं की तारीफ की। बल के महानिदेशक के. नटराजन ने कहा कि इस जहाज ने पुरानी पीढ़ी के 'आइसीजीएस वरद' का स्थान लिया है, जिसने 28 वर्षों तक सेवाएं दीं। उन्होंने कहा कि आवंटित धनराशि का 90 फीसद जहाज के भारतीयकरण पर खर्च किया गया है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 'वरद' 10,000 किलोमीटर तक बिना रुके यात्रा कर सकता है। नटराजन ने कहा कि 15 मार्च को दो इंजनों वाला हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है, जो जहाज पर लैंडिंग में सक्षम होगा। अभी तटरक्षक बल के पास 61 जहाज हैं। वर्ष 2025 तक इसकी संख्या 200 करने की योजना है। हमारे पास अभी 65 विमान हैं, जिनकी संख्या 100 की जानी है। इस दौरान चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन पी. रवींद्रन भी मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि लार्सन एंड टूब्रो ने वर्ष 2015 में भारत सरकार के साथ सात अत्याधुनिक जहाजों के लिए 1,432 करोड़ रुपये का समझौता किया था। 'वरद' इस श्रेणी का पांचवां जहाज है।

कह के रहेंगे माधव जोशी